



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 51] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 23—दिसम्बर 29, 2017 (पौष 2, 1939)

No. 51] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 23—DECEMBER 29, 2017 (PAUSA 2, 1939)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

पृष्ठ सं.

भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.....	1049
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	1093
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	11
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	2303
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.....	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.....	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.....	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).....	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को	

*अंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.....	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).....	*
भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश.....	*
भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	23741
भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस.....	*
भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	*
भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.....	2765
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस.....	2207
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के अंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक.....	*

CONTENTS

Page No.	Page No.		
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1049	by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1093	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	11	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	2303	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	23741
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	2765
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	2207
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and	*	PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 12 दिसम्बर 2017

सं. 177-प्रेज/2017—भारत के राजपत्र के भाग-I, खण्ड-1 में दिनांक 19 अगस्त, 1972 को प्रकाशित इस सचिवालय की 'वीर चक्र' पुरस्कार से संबंधित दिनांक 5 अगस्त, 1972 की अधिसूचना संख्या 94-प्रेज/72 के अँग्रेजी रूपांतरण में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है:—

क्रम संख्या 30 में

मेजर विनोद कुमार शारदा (आईसी-6715) पैराशूट रेजिमेंट—के स्थान पर

मेजर विनोद कुमार शारदा (आईसी-13715) पैराशूट रेजिमेंट—पढ़ा जाए।

पी. प्रवीण सिद्धार्थ
विशेष कार्य अधिकारी

गृह मंत्रालय

(राजभाषा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 6 दिसम्बर 2017

संकल्प

सं. 20012/02/2017-रा.भा.(नीति)-पार्ट-1—राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4(1) के अंतर्गत संसदीय राजभाषा समिति का गठन 1976 में किया गया था। समिति द्वारा राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3), राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5, हिंदी में पत्राचार, प्रकाशन, कोड-मैनुअल एवं प्रशिक्षण इत्यादि से संबंधित राष्ट्रपति के आदेशों के अनुपालन की स्थिति का मंत्रालयवार/क्षेत्रवार मूल्यांकन, केंद्र सरकार के कार्यालयों में पुस्तकों की खरीद, कम्प्यूटरीकरण और हिंदी, भर्ती नियमों में हिंदी जान की अनिवार्यता, शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थानों में हिंदी माध्यम की उपलब्धता, हिंदी विज्ञापनों पर व्यय तथा सार्वजनिक उपक्रमों के व्यावसायिक कार्यों में हिंदी के प्रयोग आदि से संबंधित प्रतिवेदन राष्ट्रपति जी को समय समय पर प्रस्तुत की गई। वर्ष 1988 में संसदीय राजभाषा समिति के प्रथम खंड पर राष्ट्रपति जी के आदेश पारित हुए और वर्ष 2017 में नौवें खंड पर राष्ट्रपति जी के आदेश संकल्प के रूप में जारी किए गए। संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन (खंड-9) की सिफारिश सं 2 पर राष्ट्रपति जी के आदेशानुसार संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन के पिछले आठ खंडों में अस्वीकृत संस्तुतियों अथवा संशोधन के साथ स्वीकृत संस्तुतियों की समीक्षा राजभाषा विभाग द्वारा की गई है। तदनुसार अधोहस्ताक्षरी को निम्नलिखित आदेश सूचित करने का निदेश हुआ है:

दूसरा खंड

[पूर्व आदेश दिनांक 29.03.1990 को संकल्प सं 12015/34/87-राभा(त.क.) द्वारा जारी]

क्र. सं.	खंड सं/ सिफारिश सं.	सिफारिश	राष्ट्रपति जी के पूर्व आदेश	राष्ट्रपति जी के परिशोधित आदेश
1	2/3 'ख'	जिन कर्मचारियों को अभी तक हिंदी टंकण अथवा हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण प्राप्त	सिफारिश के इस भाग को इस संशोधन के साथ स्वीकार किया गया है कि	इस सिफारिश पर पारित राष्ट्रपति जी

		नहीं हैं, उन्हें एक समयबद्ध योजना के अनुसार 1990 के अंत तक इसमें प्रशिक्षित कराया जाए, ताकि आवश्यकतानुसार वे हिंदी में टंकण तथा आशुलिपि का कार्य कर सकें।	समयबद्ध योजना के अनुसार 1994-95 के अंत तक हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि के प्रशिक्षण के लिए वर्तमान में शेष रहे लगभग सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाए। इसके लिए प्रत्येक वर्ष राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित वार्षिक कार्यक्रम में हिंदी आशुलिपिकों तथा देवनागरी टंककों के लक्ष्यों में प्रायः 20 प्रतिशत वृद्धि की जानी अपेक्षित होगी।	के आदेश यथावत हैं।
2	2/7 (क)	'क' तथा 'ख' क्षेत्रों के कार्यालयों में जहां केवल रोमन टेलीप्रिंटर लगे हुए हैं वहां उनके साथ-साथ देवनागरी टेलीप्रिंटर जून, 1988 तक लगाए जाने चाहिए।	यह सिफारिश संशोधन के साथ स्वीकार की गई है। चूंकि अब द्विभाषी इलैक्ट्रॉनिक टैलेक्स मशीन का विकास हो चुका है और इन मशीनों का व्यावसायिक उत्पादन भी हो रहा है, उचित यही होगा कि रोमन टेलीप्रिंटरों को द्विभाषी टैलेक्स मशीनों से बदल दिया जाए।	यह सिफारिश वर्तमान में अप्रासंगिक है। अतः स्वीकार नहीं की जाती है।
3	2/7(ख)	देवनागरी तथा रोमन के द्विभाषी इलैक्ट्रॉनिक टेलीप्रिंटर और टैलेक्स के विकास में भी तेजी लाई जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाए कि इसके विकास में तनिक भी विलम्ब नहीं किया जाए और उनके परीक्षण सफल होने के बाद वर्तमान रोमन इलैक्ट्रॉनिक टेलीप्रिंटरों की बजाए द्विभाषी इलैक्ट्रॉनिक टेलीप्रिंटर स्थापित किए जाएं। यह कार्य वर्ष 1988 के अंत तक पूरा हो जाना चाहिए।	यह सिफारिश भी संशोधन के साथ स्वीकार की गई है। द्विभाषी इलैक्ट्रॉनिक टेलीप्रिंटर और टैलेक्स के विकास का कार्य पहले ही पूरा हो चुका है और वर्तमान रोमन इलैक्ट्रॉनिक टेलीप्रिंटरों की बजाय द्विभाषी इलैक्ट्रॉनिक टैलेक्स मशीनें वर्ष 1988 के अंत तक लगाने की समय-सीमा भी पहले ही समाप्त हो चुकी है। इसलिए दूरसंचार विभाग अंग्रेजी-देवनागरी द्विभाषी टैलेक्स मशीनों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करे और यह सुनिश्चित करें कि सभी सरकारी कार्यालयों में अगले लगभग तीन वर्षों में, अर्थात् 30-9-1993 सभी टेलीप्रिंटर/टैलेक्स द्विभाषी हों। इसके लिए दूरसंचार विभाग एक समयबद्ध योजना बनाए, ताकि जहां तक एक ओर शीघ्रातिशीघ्र द्विभाषी टैलेक्स मशीनें कार्यालयों में उपलब्ध हों वहीं दूसरी ओर उन पर मुख्यतया देवनागरी में ही काम किया जाए।	यह सिफारिश वर्तमान में अप्रासंगिक है। अतः स्वीकार नहीं की जाती है।
4	2/20 (ख)	कम्प्यूटर, शब्द-संसाधक आदि की खरीद के लिए जांच बिंदु इलैक्ट्रॉनिकी विभाग को बनाया जाए।	समिति की सिफारिश इस संशोधन के साथ मान ली गई है कि कम्प्यूटर तथा शब्द संसाधक आदि की खरीद के लिए जांच बिंदु प्रत्येक विभाग का प्रशासन प्रभाग तथा इसमें किसी प्रकार की छूट	यह सिफारिश स्वीकार नहीं की जाती है।

		देने के लिए जांच बिंदु राजभाषा विभाग रहेगा।	
5	2/25	समिति ने यह सिफारिश की है कि चूंकि तार भी पत्राचार का ही रूप है इसलिए राजभाषा नियमों में किए गए प्रावधान के अनुसार 'क' तथा 'ख' क्षेत्रों में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों तथा राज्य सरकारों और उनके कार्यालयों तथा अन्य व्यक्तियों आदि को तथा 'ग' क्षेत्र में स्थित अधिसूचित कार्यालयों को सभी सरकारी तार केवल देवनागरी में ही भेजे जाएं।	समिति की सिफारिश इस संशोधन के साथ मान ली गई है कि जहां जहां देवनागरी में तार भेजने की सुविधा उपलब्ध है, वहाँ स्थित कार्यालयों में सभी तार राजभाषा विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप हिंदी में ही भिजवाए जाएं। यह सिफारिश वर्तमान में अप्रासंगिक है। अतः स्वीकार नहीं की जाती है।

चौथा खंड

[पूर्व आदेश दिनांक 28.01.1992 को संकल्प सं 12019/10/91-राभा(भा) द्वारा जारी]

क्र. सं.	खंड सं/ सिफारिश सं०	सिफारिश	राष्ट्रपति जी के पूर्व आदेश	राष्ट्रपति जी के परिशोधित आदेश
6	4/2 'ग'	समिति ने सिफारिश की है कि प्रत्येक मंत्रालय/विभाग वर्ष में एक बार अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन आयोजित करें।	समिति की यह सिफारिश इस संशोधन के साथ मान ली गई है कि वित्त मंत्रालय द्वारा इस संबंध में वर्तमान में लगाए गए प्रतिबंध को हटाने के बाद ही ऐसे सम्मेलन आयोजित किए जाएँ। इस संबंध में राजभाषा विभाग यथासमय निर्देश जारी करें।	यह सिफारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि प्रत्येक मंत्रालय/विभाग वर्ष में एक बार अखिल भारतीय आंतरिक राजभाषा सम्मेलन वित्त मंत्रालय के अद्यतन दिशा निर्देशों के अनुसार करने पर विचार करें।
7	4/6(ख)	"क" क्षेत्र में धारा 3 (3) के दस्तावेज केवल हिंदी में जारी करना समिति ने सिफारिश की है कि "क" क्षेत्र में राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) के दस्तावेज (संसद के समक्ष रखे जाने वाले कागजात को छोड़कर) केवल हिंदी में जारी किए जाएं।	राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (5) में किए गए प्रावधानों के अनुसार जब तक ऐसे सभी राज्यों के विधान मण्डलों द्वारा, जिन्होंने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, संकल्प पारित नहीं कर दिए जाते और जब तक पूर्ववर्ती संकल्पों पर विचार करने के बाद ऐसी समाप्ति के लिए संसद के हर एक सदन द्वारा संकल्प पारित नहीं कर दिया जाता, तब तक धारा 3 (3) की स्थिति यथावत् बनी रहेगी। अतः वर्तमान में समिति की उक्त सिफारिश स्वीकार करना संभव नहीं है।	यह सिफारिश स्वीकार नहीं की जाती है।

8	4/8'ख'	समिति ने सिफारिश की है कि प्रत्येक कार्यालय में गठित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष में कम से कम 6 बैठकें बुलाई जाएँ।	ऐसा करना व्यावहारिक नहीं है, इसलिए सिफारिश स्वीकार नहीं की गई। तथापि, समिति की उक्त सिफारिश के परिप्रेक्ष्य में राजभाषा विभाग, सभी मंत्रालयों/विभागों आदि से अनुरोध करे कि वे तथा उनके नियंत्रणाधीन कार्यालयों में वर्ष में 4 बैठकों (प्रत्येक तिमाही में एक) का कारगर ढंग से आयोजन करने की अनिवार्यता को सुनिश्चित करें तथा इन बैठकों में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग संबंधी वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति पर मुख्य रूप से विचार-विमर्श/समीक्षा भी सुनिश्चित करें।	इस सिफारिश पर पारित राष्ट्रपति जी के आदेश यथावत हैं।
9	4/8'ग'	समिति ने सिफारिश की है कि प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के लिए अलग-अलग हिंदी सलाहकार समिति का गठन किया जाए। उसका समय-समय पर पुनर्गठन किया जाए, वर्ष में कम से कम चार बैठकें आयोजित की जाएँ तथा समितियों की सिफारिशों पर ठोस रूप से यथासमय अनुवर्ती कार्रवाई की जाए।	समिति की यह सिफारिश इस संशोधन के साथ मान ली गई है कि जो बहुत छोटे-छोटे मंत्रालय/विभाग हैं, उनमें संयुक्त रूप से हिंदी सलाहकार समिति गठित की जाए। शेष मंत्रालयों/विभागों की अलग-अलग हिंदी सलाहकार समितियां गठित की जाएं। राजभाषा विभाग इस परिप्रेक्ष्य में पुनः समीक्षा करके नीति निर्धारित करें।	इस सिफारिश पर सातवें खंड की सिफारिश सं 16.5(च) पर पारित राष्ट्रपति जी के आदेश यथावत हैं।
10	4/9'क'	समिति ने सिफारिश की है कि भारत सरकार के प्रत्येक कार्यालय द्वारा बुलाई गई बैठकों, सम्मेलनों, संगोष्ठियों की कार्यसूची तथा कार्यवृत्त आदि एवं अन्य पत्राचार में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाए।	यह सिफारिश इस संशोधन के साथ मान ली गई है कि केवल 'क' क्षेत्र में परिचालित होने वाली कार्यसूची/कार्यवृत्त आदि एवं संबंधित पत्राचार केवल हिंदी में परिचालित किए जा सकते हैं। इस संबंध में राजभाषा विभाग आवश्यक निदेश जारी करें।	इस सिफारिश पर पारित राष्ट्रपति जी के आदेश यथावत हैं।
11	4/10	समिति ने यह भी सिफारिश की है कि केंद्रीय सरकार के कार्यालयों द्वारा 'क' तथा 'ख' क्षेत्र को भेजे जाने वाले तार देवनागरी में भेजे जाएं और 'ग' क्षेत्र में भी हिंदी में तार भेजने की शुरूआत की जाए।	तार देवनागरी में भेजने के संबंध में समिति की सिफारिश आंशिक संशोधन के साथ मान ली गयी है। उपलब्ध संसाधनों को देखते हुए राजभाषा विभाग वार्षिक कार्यक्रम में 'क' तथा 'ख' क्षेत्र की तरह 'ग' क्षेत्र को भेजे जाने वाले तारों का लक्ष्य निर्धारित करें और सभी मंत्रालयों/विभागों आदि को निदेश जारी करके उनका अनुपालन सुनिश्चित कराये।	यह सिफारिश वर्तमान में अप्रासंगिक है। अतः स्वीकार नहीं की जाती है।
12	4/16	समिति ने सिफारिश की है कि सभी कार्यालयों में उपलब्ध रजिस्टरों और सभी वर्गों के अधिकारियों और कर्मचारियों की	समिति की यह सिफारिश आंशिक संशोधन के साथ स्वीकार कर ली गई है। 'क' व 'ख' क्षेत्र में स्थित केंद्रीय	इस सिफारिश पर पारित राष्ट्रपति जी के आदेश यथावत हैं।

		सेवा-पुस्तिकाओं के शीर्षक द्विभाषी होने चाहिए और उनमें प्रविष्टियां हिंदी में होनी चाहिए। इनके अतिरिक्त सभी क्षेत्रों में अधिकारियों और कर्मचारियों की वर्दियों पर लगाए जा रहे बिल्ले/प्रतीक चिह्न आदि भी हिंदी में अवश्य होने चाहिए, वर्दियों पर काढ़े जाने वाले नाम भी दोनों भाषाओं—हिंदी और अंग्रेजी में होने चाहिए। इसके अतिरिक्त 'क' और 'ख' क्षेत्र में भेजे जाने वाले लिफाफों पर पते अनिवार्य रूप से हिंदी में ही लिखे जाएं।	सरकार के कार्यालयों में रखे जाने वाले रजिस्टरों/सेवा-पुस्तिकाओं में प्रविष्टियां हिंदी में की जाएं तथा 'ग' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में ऐसी प्रविष्टियां यथासम्भव हिंदी में की जाएं। इस संबंध में राजभाषा विभाग द्वारा पूर्व में जारी किए गए निदेश पुनः सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों आदि को परिचालित किए जाएं, ताकि समिति की इन सिफारिशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।	
13	4/19(ख)	समिति ने अपने प्रतिवेदन के दूसरे और तीसरे खंड में की गई अपनी इस सिफारिश को दोहराया है कि देश की एकता और अखंडता के परिप्रेक्ष्य में राजभाषा विभाग के दायित्व व महत्व को देखते हुए राजभाषा विभाग का पुनर्गठन करे, उसे और अधिक सुदृढ़ बनाए और उसे एक मंत्रालय का दर्जा दे, जिससे भारत सरकार की राजभाषा नीति को उसके सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/उपक्रमों तथा स्वायत्त निकायों में प्रभावी और कारगर ढंग से कार्यान्वित किया जा सके।	गृह मंत्रालय के महत्व, कार्य-क्षेत्र, एवं विभिन्न राज्य सरकारों के साथ इसके सम्पर्क को देखते हुए राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के ही अंतर्गत रखा जाए। अतः समिति की उक्त सिफारिश स्वीकार नहीं की गई है। तथापि, समिति की सिफारिशों के अनुसार राजभाषा विभाग को और अधिक सुदृढ़ और सक्षम बनाया जाये।	इस सिफारिश पर पारित राष्ट्रपति जी के आदेश यथावत हैं।

पांचवा खंड

[पूर्व आदेश दिनांक 24.11.1998 को संकल्प सं ।।/20012/4/92-राभा(नी-1) द्वारा]

क्र. सं.	खंड सं/ सिफारिश सं.	सिफारिश	राष्ट्रपति जी के पूर्व आदेश	राष्ट्रपति जी के परिशोधित आदेश
14	5/1	गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग का पुनर्गठन करके उसे पूर्ण मंत्रालय का दर्जा देते हुए अधिक सुदृढ़ और सक्षम बनाने के लिए अविलम्ब कर्तवाई की जानी चाहिए।	राजभाषा विभाग के वर्तमान कार्य क्षेत्र के सापेक्ष इसके लिए अलग से संपूर्ण मंत्रालय बनाना वर्तमान में व्यावहारिक प्रतीत नहीं होता है।	इस सिफारिश पर पारित राष्ट्रपति जी के आदेश यथावत हैं।
15	5/5	महामहिम राष्ट्रपति के आदेशों की अवहेलना करने वाले हिंदी में प्रवीण अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कर्तवाई की जाए।	राजभाषा विभाग ऐसे आदेश जारी करे कि सभी मंत्रालय/विभाग अपने वरिष्ठ अधिकारियों, विशेष कर उप सचिव एवं समकक्ष तथा उससे वरिष्ठ अधिकारियों को राजभाषा हिंदी में कार्य करने के लिए विशेष तौर पर प्रेरित एवं उत्साहित करे।	इस सिफारिश पर पारित राष्ट्रपति जी के आदेश यथावत हैं।
16	5/16	उच्च न्यायालयों के निर्णय, डिक्रियों व आदेशों में राज्य की राजभाषा अथवा हिंदी का प्रयोग किया जाना चाहिए। किंतु यह व्यवस्था भी की जानी चाहिए कि प्रत्येक निर्णय का प्राधिकृत अनुवाद दोनों भाषाओं	इस सिफारिश पर संविधान तथा राजभाषा अधिनियम 1963 के वर्तमान प्रावधानों के अनुसार कर्तवाई करने की वर्तमान नीति पर्याप्त है।	इस सिफारिश पर पारित राष्ट्रपति जी के आदेश यथावत हैं।

		में उपलब्ध हो। जब तक अंग्रेजी का प्रचलन बना रहता है। तब तक इनका प्राधिकृत अनुवाद अंग्रेजी में सुलभ कराने की व्यवस्था की जा सकती है। तथापि उच्च न्यायालयों की कार्यवाहियों राज्य की राजभाषा में अथवा हिंदी में या अंग्रेजी में की जा सकती है।		
17	5/17	अहिंदी भाषी राज्यों में भी संबंधित राज्य की राजभाषा में दिए गए निर्णयों का प्राधिकृत हिंदी अनुवाद कराने के लिए संघ सरकार संबंधित राज्य सरकारों को विशेष वित्तीय सहायता प्रदान करें।	अहिंदी भाषी राज्यों में भी संबंधित राज्य की राजभाषा में दिए गए निर्णयों का प्राधिकृत पाठ हिंदी में उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकारें स्वयं अपने वित्तीय संसाधनों का श्रेष्ठतम उपयोग कर इस दिशा में कार्य करें।	इस सिफारिश पर पारित राष्ट्रपति जी के आदेश यथावत हैं।

छठा खंड

[पूर्व आदेश दिनांक 03.09.2004 को संकल्प सं 12021/02/2003-रा.भा.(का-2) द्वारा जारी]

क्र. सं.	खंड सं/ सिफारिश सं०	सिफारिश	राष्ट्रपति जी के पूर्व आदेश	राष्ट्रपति जी के परिशोधित आदेश
18	6/11.5.10	शब्दकोश, शब्दावली, सहायक तथा संदर्भ साहित्य और अन्य हिंदी पुस्तकों की खरीद की तरफ विशेष ध्यान दिया जाए व इन पर लक्ष्य के अनुसार राशि खर्च की जाए।	समिति की यह सिफारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार कर ली गई है कि पुस्तकालयों के लिए उपलब्ध धनराशि में से जर्नल व संदर्भ साहित्य की खरीद किए जाने के बाद बची राशि का 50% हिंदी पुस्तकों की खरीद पर खर्च किया जाए। राजभाषा विभाग द्वारा परिचालित हिंदी की स्तरीय पुस्तकों की सूची में उल्लिखित सभी पुस्तकों को खरीदना आवश्यक है। राजभाषा विभाग समय-समय पर हिंदी की स्तरीय पुस्तकों की एक सूची सभी मंत्रालयों/विभागों को उपलब्ध करवाएगा।	यह सिफारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि इस सिफारिश पर संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन के खंड-9 की सिफारिश सं 52 पर पारित आदेशानुसार कार्रवाई की जाए।
19	6/11.5.13	सभी भर्ती परिक्षाओं में अंग्रेजी के प्रश्नपत्र की अनिवार्यता समाप्त की जाए। सभी भर्ती परीक्षाओं का माध्यम हिंदी हो। जहां अपरिहार्य हो वहीं अभ्यर्थी को उत्तर देने के लिए अंग्रेजी माध्यम का विकल्प दिया जाए। साक्षात्कार के लिए भी यहीं नियम लागू हो।	साक्षात्कार में हिंदी का विकल्प देने के लिए पहले से आदेश विद्यमान हैं। लेकिन अंग्रेजी के प्रश्न-पत्र की अनिवार्यता समाप्त करने तथा सभी भर्ती परीक्षाओं का माध्यम हिंदी करने संबंधी सिफारिश स्वीकार नहीं की गई क्योंकि यह संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित राजभाषा संकल्प: 1968 के प्रतिकूल है।	इस सिफारिश पर पारित राष्ट्रपति जी के आदेश यथावत हैं।
20	6/11.5.17	कई नगरों में स्थित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के सदस्यों की संख्या बहुत अधिक है। अतः समिति का सुझाव है कि इन्हें विभाजित कर इनके सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या 40 रखी जाए	समिति की यह सिफारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार कर ली गई है कि जिन समितियों की सदस्य संख्या 150 या इससे अधिक हो, उन्हें दो भागों में बांटा जाए। राजभाषा विभाग द्वारा इस	यह सिफारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार की है कि जिन नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों

		और तदनुसार दो या इससे अधिक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां गठित की जाएं।	आशय के निदेश जारी किए जाएं।	में सदस्यों की संख्या 50 से अधिक है उन्हें दो भागों में विभाजित किया जाए ताकि अधिकतम निर्धारित संख्या 50 से अधिक न हो।
21	6/11.6.4	कहीं से भी हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाने की व्यवस्था की जाए।	समिति की यह सिफारिश स्वीकार नहीं की गई, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 346 में निहित प्रावधानों के अनुसार पत्रादि में राजभाषा का प्रयोग किया जाना है।	यह सिफारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि सभी मंत्रालय/विभाग राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 के अनुसार कार्रवाई करें।
22	6/11.6.8	राज्य स्तर पर सभी इलेक्ट्रॉनिक यंत्र/संयंत्र/कम्प्यूटर आदि द्विभाषी रूप में या केवल हिंदी में उपलब्ध कराये जाएं और इनका भरपूर इस्तेमाल हिंदी कार्य के लिए किया जाए।	समिति की यह सिफारिश स्वीकार नहीं की गई।	इस सिफारिश पर पारित राष्ट्रपति जी के आदेश यथावत हैं।
23	6/11.6.9	केवल रोमन के टाइपराइटरों/इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों आदि की खरीद पर प्रतिबंध लगाया जाए।	समिति की उक्त सिफारिश स्वीकार नहीं की गई।	यह सिफारिश वर्तमान में अप्रासंगिक है। अतः स्वीकार नहीं की जाती है।
24	6/11.6.10	केंद्र सरकार के कार्यालयों आदि को टेलेक्स, टेलीप्रिंटर आदि पर सूचनाएँ हिंदी में भिजवाने की व्यवस्था की जाए और अधिकाधिक तारफ़ेक्स आदि भी देवनागरी में ही भिजवाने की व्यवस्था की जाए।	समिति की उक्त सिफारिश स्वीकार नहीं की गई।	यह सिफारिश वर्तमान में अप्रासंगिक है। अतः स्वीकार नहीं की जाती है।
25	6/11.10.3	प्रवीणता प्राप्त व हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों को कार्यशालाओं के माध्यम से हिंदी में काम करने का प्रशिक्षण देने के बाद उनसे हिंदी में कार्य लिया जाए। वे हिंदी में अपना काम शुरू करते हैं तो उन्हें स्थायी रूप से अतिरिक्त वेतन वृद्धि दी जानी चाहिए।	ऐसा करना व्यावहारिक नहीं है। अतः समिति की यह सिफारिश स्वीकार नहीं की गई है।	इस सिफारिश पर पारित राष्ट्रपति जी के आदेश यथावत हैं।
26	6/11.10.6	हिंदी में काम न करने पर जो प्रविष्टि उनकी सेवा पंजिका में हो, उनकी गोपनीय वार्षिक रिपोर्ट में भी उनके अधिकारी द्वारा यह लिखा जाए कि इन्होंने प्रशिक्षण व योग्यता हिंदी में प्राप्त कर ली है तथा इन्हें राजभाषा नियम 1976 के नियम 8 (4) के	वर्तमान में दंड की कोई व्यवस्था नहीं है। अतः समिति की उक्त सिफारिश स्वीकार नहीं की गई।	इस सिफारिश पर पारित राष्ट्रपति जी के आदेश यथावत हैं।

		अंतर्गत सरकारी कामकाज हिंदी में करने के आदेश भी दे दिए गए हैं फिर भी हिंदी में काम नहीं कर रहे हैं। यह राजभाषा नियमों की अवहेलना है। इस बात का ध्यान संबंधित कर्मचारी की अगली तरक्की के समय पर विशेष रूप से रखा जाए।	
27	6/11.10.7	जिस कर्मचारी को भारत सरकार के मंत्रालय/अधीनस्थ कार्यालय/संबद्ध कार्यालय/उपक्रम आदि, कार्यालय समय में प्रशिक्षण के लिए हिंदी, हिंदी टंकण/हिंदी आशुलिपि/अनुवाद प्रशिक्षण/कार्यशालाओं में प्रशिक्षण लेने के लिए भेजते हैं, वह नियमित रूप से प्रशिक्षण लें और प्रशिक्षण में उत्तीर्ण करने के बाद उनके लिए अपने सरकारी काम का 50 प्रतिशत कार्य हिंदी में करना अनिवार्य हो। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो जितने दिन उन्होंने प्रशिक्षण लिया और उसके प्रशिक्षण पर आने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति उस कर्मचारी के वेतन से कटौती करके करनी चाहिए।	वर्तमान में दंड की कोई व्यवस्था नहीं है। अतः समिति की उक्त सिफारिश स्वीकार नहीं की गई।
28	6/11.10.8	जो व्यक्ति हिन्दी में अपना सारा कार्य करता है और वह किसी विभागीय परीक्षा में भाग लेता है तो उसके साक्षात्कार के समय उसको हिंदी में कार्य करने के लिए अतिरिक्त अंक दिये जाने चाहिए और उसे विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा भी विशेष वरीयता दी जानी चाहिए।	भारत एक बहुभाषी देश है। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी सभी भाषा समूहों से आते हैं। अतएव ऐसा भेदभाव करना संभव नहीं है। समिति की यह सिफारिश स्वीकार नहीं की गई।
29	6/11.10.15	सरकारी कामकाज में राजभाषा के प्रगामी प्रयोग संबंधी कार्य पर निगरानी का कार्य कम से कम संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी को सौंपा जाए।	समिति की यह सिफारिश स्वीकार नहीं की गई क्योंकि सभी कार्यालयों में संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी नहीं होते हैं। अतः वर्तमान व्यवस्था पर्याप्त है।
30	6/11.10.19	राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8(4) को इस प्रकार संशोधित किया जाए जिसमें हिंदी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों/कर्मचारियों को अपना सारा काम हिंदी में करने के लिए आदेश दिये जा सके तथा हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए काम की कुछ मर्दं निर्धारित कर दी जाएँ जिन्हें वे हिंदी में करें।	राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8(4) के अंतर्गत वर्तमान व्यवस्था पर्याप्त है। अतः समिति की यह सिफारिश स्वीकार नहीं की गई है।
31	6/11.10.21	द्विभाषी इलेक्ट्रानिक यंत्रों पर किए जाने वाले कार्य में से हिंदी के कार्य की प्रतिशतता निर्धारित की जाए।	राजभाषा हिंदी में कार्य करने के लिए वार्षिक कार्यक्रम में विभिन्न मर्दों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं।

		तदनुसार ही द्विभाषी इलेक्ट्रानिक उपकरणों पर हिंदी में कार्य किया जाना है। इसके लिए अलग से प्रतिशत निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है।	
32	6/11.10.22	'क' और 'ख' क्षेत्र में स्थित भारत सरकार के कार्यालयों में केवल हिंदी में छपे या तैयार किए फॉर्म्स और मानक मसौदों का उपयोग किया जाए।	राजभाषा नियम, 1976 के नियम 11 के अंतर्गत वर्तमान व्यवस्था पर्याप्त है। अतः समिति की उक्त सिफारिश स्वीकार नहीं की गई।
33	6/11.10.23	'क' और 'ख' क्षेत्र में स्थित भारत सरकार के कार्यालयों में मोहरों, नामपट, साइनबोर्ड, सीलें, पत्रशीर्ष, वाहनों पर लिखे जाने वाले कार्यालय के विवरण और विजिटिंग कार्ड केवल हिंदी में तैयार किए जाएँ।	राजभाषा नियम, 1976 के नियम 11 के अंतर्गत वर्तमान व्यवस्था पर्याप्त है। अतः समिति की उक्त सिफारिश स्वीकार नहीं की गई।
34	6/11.10.25	राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा (3) में संशोधन किए जाए जिससे 'क' तथा 'ख' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों को उक्त धारा के अंतर्गत जारी किए जाने वाले कागजात केवल हिंदी में जारी किए जा सकें।	राजभाषा अधिनियम की धारा 3(5) में निहित प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में ऐसा किया जाना संभव नहीं है। अतः समिति की यह सिफारिश स्वीकार नहीं की गई है।
35	6/11.10.32	हिंदी दिवस वर्ष में एक बार मनाने के अलावा प्रत्येक कार्यालय द्वारा सप्ताह में कम से कम एक दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाए। उस दिन कार्यालय का सारा कार्य हिंदी में ही किया जाए। किसी विशेष मामले में यदि उस दिन कोई कार्य अंग्रेजी में करना अनिवार्य हो जाए तो उस पत्र/आदेश आदि पर संबंधित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर हिंदी में ही किए जाएं।	ऐसा करना व्यावहारिक नहीं है। संघ का राजकीय कार्य हिंदी में करने के लिए राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। अतएव यह सिफारिश स्वीकार नहीं की गई।

सातवाँ खंड

[पूर्व आदेश दिनांक 13.07.2005 को संकल्प सं 11011/5/2003-रा.आ.(अनु.) द्वारा जारी]

क्र. सं.	खंड सं/ सिफारिश सं.	सिफारिश	राष्ट्रपति जी के पूर्व आदेश	राष्ट्रपति जी के परिशोधित आदेश
36	7/16.5 'क'	केंद्रीय हिंदी समिति का पुनर्गठन निश्चित समय पर प्रत्येक तीन वर्ष पर अवश्य किया जाए।	यह सिफारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार कर ली गई है कि केंद्रीय हिंदी समिति का कार्यकाल सामान्यतः 3 वर्ष का होगा, किंतु विशेष परिस्थितियों में इसका कार्यकाल बढ़ाया अथवा कम भी किया जा सकता है।	इस सिफारिश पर पारित राष्ट्रपति जी के आदेश यथावत हैं।
37	7/16.5 'ग'	केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए संसदीय राजभाषा समिति के उपाध्यक्ष तथा तीनों उपसमितियों के संयोजकों को विशेष रूप से आमंत्रित किया जाए।	केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति केवल सरकारी अधिकारियों की समिति है। अतः यह सिफारिश स्वीकार्य नहीं की गई।	इस सिफारिश पर पारित राष्ट्रपति जी के आदेश यथावत हैं।

38	7/16.5 'च'	हिंदी सलाहकार समितियों का गठन/पुनर्गठन सही समय पर होना चाहिए तथा बैठकें नियमित रूप से प्रत्येक तिमाही में आयोजित की जानी चाहिए।	यह सिफारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार कर ली गई है कि सभी मंत्रालय/विभाग हिंदी सलाहकार समिति का गठन/पुनर्गठन समय पर करे और वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार हिंदी सलाहकार समिति की बैठकें करें।	इस सिफारिश पर पारित राष्ट्रपति जी के आदेश यथावत हैं।
39	7/16.5 'ठ'	नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष में तीन बैठकें समिति के अध्यक्ष की अध्यक्षता में अलग-अलग कार्यालयों में आयोजित की जाए तथा अंतिम बैठक समिति के अध्यक्ष के कार्यालय में ही आयोजित की जाएं और उसमें राजभाषा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहें, ताकि वर्ष भर की गतिविधियों और प्रगति की समीक्षा की जा सके और पाई गई कमियों को सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए और सामूहिक प्रयास से दूर कर लिया जाए।	यह सिफारिश स्वीकार्य नहीं पाई गई। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें अलग-अलग स्थानों पर आयोजित करना, बैठक का स्थान व अन्य संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है।	इस सिफारिश पर पारित राष्ट्रपति जी के आदेश यथावत हैं।
40	7/16.5 'ड'	विभिन्न नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बड़ी सदस्य संख्या को देखते हुए ऐसे नगरों में जहां एक ही नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति है, वहां नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति को तीन उप समितियों में विभाजित कर तीन अलग-अलग संयोजक बनाए जाएं एवं उनका अध्यक्ष एक ही हो ताकि सभी सदस्य कार्यालयों में हिंदी के अनुकूल वातावरण बने और राजभाषा नियमों के प्रति जागरूकता आए।	संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन के खंड-6 में की गई सिफारिश सं. 11.5.17 पर आदेश दिया गया है कि ऐसी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों को, जिनकी सदस्य संख्या 150 या इससे अधिक है, दो भागों में बांटा जाए, इस व्यवस्था में अभी परिवर्तन करना सामयिक नहीं है।	यह सिफारिश इस संशोधन के स्वीकार की जाती है कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों में सदस्यों की संख्या अधिकतम 50 रखी जाए और इससे अधिक होने पर व्यावहारिकता के आधार पर उन्हें विभाजित किया जाए। विभाजन की स्थिति में हर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष व सचिव अलग होंगे।
41	7/16.7 'ख'	गैर सरकारी प्रकाशकों को सरकारी प्रकाशनों के प्रकाशन की अनुमति देते समय यह पाबंदी अवश्य लगाई जाए कि वे केवल अंग्रेजी भाषा में उन्हें प्रकाशित न करें बल्कि इन प्रकाशनों को डिग्लॉट रूप में हिंदी-अंग्रेजी में अनिवार्य रूप से छापें।	यह सिफारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार की गई है कि जहां तक सभव हो सके सभी सरकारी प्रकाशनों को डिग्लॉट रूप में छपवाया जाए।	इस सिफारिश पर पारित राष्ट्रपति जी के आदेश यथावत हैं।
42	7/16.7 'घ'	अवर सचिव व इसके ऊपर के स्तर के अधिकारियों की प्रबंधकीय दक्षता के उन्नयन हेतु आयोजित सेवाकालीन प्रशिक्षणों को हिंदी	यह सिफारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार कर ली गई है कि सभी सेवाकालीन प्रशिक्षणों के प्रमुखतः हिंदी के आदेश यथावत	इस सिफारिश पर पारित राष्ट्रपति जी के आदेश यथावत

		में आयोजित किया जाए।	भाषा के माध्यम से और गैणतः मिली-जुली भाषा के माध्यम से चलाया जाए।	हैं।
43	7/16.7 'छ'	अधिकारियों के लिए उनके द्वारा हिंदी में दिए जाने वाले डिक्टेशन व अन्य कार्यों के लिए राजभाषा विभाग वार्षिक कार्यक्रम में स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें तथा उनका अभिलेख(लेखा-जोखा) रखना अनिवार्य किया जाए तथा मुख्यालय/मंत्रालय स्तर पर इसकी समीक्षा सुनिश्चित की जाए।	यह सिफारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार की गई है कि जिन अधिकारियों के पास हिंदी आशुलिपिकों की सुविधा उपलब्ध है वे उनकी सेवाओं का पूरा उपयोग करें। राजभाषा विभाग द्वारा वार्षिक कार्यक्रम में अधिकारियों द्वारा हिंदी में दिए जाने वाले डिक्टेशन के लिए लक्ष्य निर्धारित किया जाए।	यह सिफारिश स्वीकार की जाती है।
44	7/16.8 'ग'	राजभाषा हिंदी में प्रारूपण करने वालों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाए।	यह सिफारिश स्वीकार नहीं की गई है क्योंकि प्रारूपकार नियमित सरकारी कर्मचारी हैं।	इस सिफारिश पर पारित राष्ट्रपति जी के आदेश यथावत हैं।
45	7/16.9 (क)	किसी गैर-सरकारी व्यक्ति को भारत सरकार के हिंदी सलाहकार के पद पर प्रतिष्ठित किया जाए जो न केवल संसदीय राजभाषा समिति में स्थायी रूप से आमंत्रित रहेंगे, बल्कि केंद्रीय हिंदी समिति के भी स्थायी सदस्य रहेंगे। इसके लिए हिंदी के किसी विद्यवान या हिंदी के प्रचार-प्रसार से जुड़े व अनुभवी व्यक्ति की सेवाएं लेना उचित होगा।	यह सिफारिश विचाराधीन है।	यह सिफारिश स्वीकार नहीं की जाती है।
46	7/16.10 (1)	प्राइवेट प्रकाशकों को सरकारी प्रकाशन छापने के पूर्व उन्हें सरकार द्वारा प्रकाशन के अधिकार (कापीराइट) की अनुमति प्राप्त करने का प्रावधान किया जाना चाहिए। यदि ऐसा प्रावधान पहले से विद्यमान है तो सरकार अथवा इसके किसी विभाग द्वारा कापीराइट हस्तांतरित करने की अनुमति देने के समय संबंधित सामग्री को द्विभाषी मुद्रित कराने की शर्त का प्रावधान किया जाना चाहिए। यदि पुस्तक के आकार के कारण डिग्लॉट रूप में छापना असुविधाजनक हो तो ऐसी स्थिति में अंग्रेजी संस्करण के आवरण पृष्ठ पर विशेष रूप से यह उल्लेख किया जाए कि प्रकाशक/वितरक के पास इस संस्करण का हिंदी रूपांतरण भी उपलब्ध है।	यह सिफारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार कर ली गई है कि जहां तक संभव हो सके सभी सरकारी प्रकाशनों को डिग्लॉट रूप में छपवाया जाए।	इस सिफारिश पर पारित राष्ट्रपति जी के आदेश यथावत हैं।
47	7/16.12 (क)	विनिवेश के संदर्भ में समिति यह सिफारिश करती है कि जिस भी उपक्रम में सरकारी भागीदारी हो, चाहे कम या ज्यादा, राजभाषा नीति यथावत लागू रहेगी।	इस सिफारिश पर राजभाषा विभाग संबंधित मंत्रालयों से चर्चा करें।	यह सिफारिश स्वीकार की जाती है।
48	7/16.12 (ख)	बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ-साथ स्वदेशी कंपनियों, जो अपने उत्पाद की बिक्री अथवा उसके प्रचार-प्रसार के लिए हिंदी का सहारा	राजभाषा विभाग इस विषय में संबंधित पक्षों से चर्चा करें।	यह सिफारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है।

	ले रही है, उनके लिए यह बाध्य किया जाए कि वे सरकार के साथ पत्राचार हिंदी में ही करें साथ ही सरकार भी उनके साथ पत्राचार हिंदी में ही करें।	कि प्रेरणा और प्रोत्साहन के माध्यम से कार्रवाई की जाए।
--	--	--

आंठवाँ खंड

[पूर्व आदेश दिनांक 02.07.2008 को संकल्प सं ।/20012/07/2005-राजा(नीति-1) द्वारा जारी]

क्र. सं.	खंड सं/ सिफारिश सं.	सिफारिश	राष्ट्रपति जी के पूर्व आदेश	राष्ट्रपति जी के परिशोधित आदेश
49	8/1'घ'	हिंदी सलाहकार समिति की वर्ष में कम से कम तीन बैठकें आयोजित की जाएं।	यह सिफारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि सभी मंत्रालय/विभाग हिंदी सलाहकार समिति की वर्ष में कम से कम दो बैठकें तो अवश्य आयोजित करें। इससे अधिक बैठकों के आयोजन के लिए भी सभी प्रयास करें।	इस सिफारिश पर पारित राष्ट्रपति जी के आदेश यथावत हैं।
50	8/7	'ग' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के लिए भी रजिस्टरों में प्रविष्टियों का न्यूनतम प्रतिशत निर्धारित किया जाए और रजिस्टरों में हिंदी में यथासंभव प्रविष्टियों जैसा प्रावधान समाप्त कर दिया जाए।	सिफारिश आंशिक संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि 'ग' क्षेत्र में स्थित सरकारी कार्यालय इस दिशा में अपने यथासंभव प्रयास जारी रखें।	इस सिफारिश पर पारित राष्ट्रपति जी के आदेश यथावत हैं।
51	8/12	समिति ने चौथे खंड में सिफारिश की थी कि 'क' क्षेत्र में केवल संसद के समक्ष रखे जाने वाले कागजात को छोड़कर सभी कागजात केवल हिंदी में जारी किए जाएं। 'क' क्षेत्र में अद्यतन स्थिति को देखते हुए समिति पुनः यह सिफारिश करती है कि उपर्युक्त कागजात के अतिरिक्त राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी कागजात के संबंध में अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त कर दी जाए। जिन राज्यों में अभी तक हिंदी को राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है गृह मंत्रालय द्वारा पहल करके उनसे चर्चा की जाए कि वह अपने राज्य की राजभाषा के साथ-साथ हिंदी को भी राजभाषा का दर्जा प्रदान करें।	वर्तमान में इस सिफारिश के संबंध में राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(5) में किए गए प्रावधानों के अनुसार अनुपालन ही जारी रहे।	इस सिफारिश पर पारित राष्ट्रपति जी के आदेश यथावत हैं।
52	8/13	राजभाषा विभाग, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के माध्यम से हिंदी/भाषा/आशुलिपि/टंकण प्रशिक्षण का सघन अभियान चलाकर प्रशिक्षण सुविधाओं को प्रत्येक कार्यालय तक पहुँचाएँ।	यह सिफारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि भारत सरकार के सभी कार्मिकों को राजभाषा विभाग के अधीनस्थ कार्यालय, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रशिक्षण देने हेतु नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां अपना यथासंभव सहयोग दें।	इस सिफारिश पर पारित राष्ट्रपति जी के आदेश यथावत हैं।

53	8/17	नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के प्रभावी संचालन हेतु नराकास सचिवालय को स्थाई तौर पर अतिरिक्त मानव संसाधन एवं अन्य आधुनिक सुविधाओं से युक्त बनाया जाना चाहिए।	सिफारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत ही नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां अपने सदस्य-कार्यालयों के सहयोग से उनके पास उपलब्ध आंतरिक संसाधनों से ही समितियों के प्रभावी संचालन हेतु आवश्यक सुविधाएं जुटाएं।	इस सिफारिश पर पारित राष्ट्रपति जी के आदेश यथावत हैं।
54	8/18	प्रत्येक क्षेत्र में राजभाषा गतिविधियों को बढ़ाने के उद्देश्य से हर वर्ष नराकास अध्यक्षों का एक सम्मेलन आयोजित किया जाना चाहिए तथा राजभाषा नीति व लक्ष्यों के निर्धारण के मामले में इनकी भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए।	सिफारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि इस प्रकार की बैठकें वार्षिक आधार पर क्षेत्रीय स्तर पर आयोजित की जाएं।	इस सिफारिश पर पारित राष्ट्रपति जी के आदेश यथावत हैं।
55	8/19	हिंदीतर भाषी क्षेत्रों विशेषकर तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक जैसे राज्यों में हिंदी समाचार-पत्रों/पत्रिकाओं के प्रकाशन तथा इनसे जुड़े हिंदी पत्रकारों के प्रोत्साहन हेतु विशेष योजनाएं चलाई जाएं।	सिफारिश स्वीकार नहीं की जाती है।	इस सिफारिश पर पारित राष्ट्रपति जी के आदेश यथावत हैं।
56	8/20	नराकास की बैठकों में राजभाषा विभाग, नई दिल्ली के वरिष्ठ अधिकारी का प्रतिनिधित्व अनिवार्य किया जाए।	सिफारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि नराकास की बैठकों में राजभाषा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का प्रतिनिधित्व यथासंभव सुनिश्चित किया जाए।	इस सिफारिश पर पारित राष्ट्रपति जी के आदेश यथावत हैं।
57	8/21	क्षेत्र 'ग' में स्थित प्रत्येक केंद्रीय कार्यालय में कम से कम एक हिंदी स्टाफ की तैनाती अनिवार्य की जाए।	इस सिफारिश के संबंध में राजभाषा विभाग द्वारा न्यूनतम स्टाफ की तैनाती संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाए।	इस सिफारिश पर पारित राष्ट्रपति जी के आदेश यथावत हैं।
58	8/28	राजभाषा से संबन्धित नियमों इत्यादि के कार्यान्वयन को उचित गंभीरता से लेने के उद्देश्य से केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में कार्रवाई की जाए और सभी विभागों के सचिव इस समिति के सदस्य हों।	सिफारिश विचाराधीन है।	वर्तमान में सचिव राजभाषा की अध्यक्षता में बैठकें होती हैं जिसमें परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। अतः यह सिफारिश स्वीकार नहीं की जाती है।
59	8/29	तकनीकी, वैज्ञानिक, शोध व अनुसंधान से जुड़े विभिन्न विषयों से संबंधित हिंदी साहित्य को एक जगह उपलब्ध कराने के लिए सरकार शीघ्र ही वैज्ञानिक एवं तकनीकी हिंदी पुस्तक-बैंकों की स्थापना करे जो ऐसी पुस्तकों/साहित्य को प्रयोक्ताओं एवं उपभोक्ता संस्थानों को उपलब्ध कराएं अथवा उन्हें प्राप्ति स्रोतों की जानकारी दें।	सिफारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि सभी मंत्रालय/विभाग अपने कार्य से संबंधित तकनीकी, वैज्ञानिक शोध, अनुसंधान से जुड़े विभिन्न विषयों पर पर्याप्त हिंदी साहित्य की उपलब्धता सुनिश्चित करें एवं उनके प्राप्ति स्रोतों की जानकारी अपनी वेबसाइट के साथ-साथ अन्य	इस सिफारिश पर पारित राष्ट्रपति जी के आदेश यथावत हैं।

			संभव साधनों द्वारा प्रयोक्ताओं एवं उपयोक्ताओं को दें।	
60	8/34	वार्षिक कार्यक्रम 2004-05 में तथा उसके पश्चात् राजभाषा विभाग ने पुस्तकों की खरीद के संबंध में पूर्व निर्धारित लक्ष्य में संशोधन कर इसमें जर्नल्स एवं मानक संदर्भ पुस्तकों की खरीद पर व्यय को शामिल नहीं किया है। समिति इस संशोधन पर पुनर्विचार की आवश्यकता महसूस करती है, क्योंकि यदि यह छूट अनिवार्य समय के लिए लागू रही तो इसका हिंदी के दूरगामी उद्देश्य पर विपरीत असर पड़ेगा।	वर्तमान में यथास्थिति बनाए रखी जाए।	इस सिफारिश पर पारित राष्ट्रपति जी के आदेश यथावत हैं।
61	8/36	उप सचिव या उन उच्चाधिकारियों के लिए जिन्हें कम्प्यूटर उपलब्ध करवाया गया है, कम्प्यूटरों पर हिंदी के उपयोग का कम से कम एक सप्ताह का क्रेश पाठ्यक्रम आयोजित किया जाए और 'क', 'ख' तथा 'ग' क्षेत्रों के आधार पर उनके लिए देवनागरी में कम्प्यूटर पर कार्य का लक्ष्य भी निर्धारित किया जाए।	सिफारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार है कि उप सचिव/उच्चाधिकारियों के लिए लघु अवधि के दृतगामी पाठ्यक्रम आयोजित किए जाए और वे कम्प्यूटर पर देवनागरी में अधिक से अधिक कार्य करें।	इस सिफारिश पर पारित राष्ट्रपति जी के आदेश यथावत हैं।
62	8/46	केंद्रीय सरकार की भर्ती हेतु आयोजित स्पर्धात्मक परीक्षाओं में कम से कम मैट्रिक अथवा समकक्ष स्तर का हिंदी का एक अनिवार्य प्रश्न पत्र तैयार किया जाए, जिसमें उत्तीर्ण हुए बिना अभ्यर्थी को असफल माना जाए।	सिफारिश स्वीकार नहीं की गई है।	इस सिफारिश पर पारित राष्ट्रपति जी के आदेश यथावत हैं।
63	8/47	केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के तहत बड़े-बड़े मंत्रालयों/विभागों में निदेशक (राजभाषा) के पद यथावत बने रहें और संयुक्त सचिव (राजभाषा) के पद सृजित करने पर भी विचार किया जाए।	सिफारिश स्वीकार नहीं की गई है।	इस सिफारिश पर पारित राष्ट्रपति जी के आदेश यथावत हैं।
64	8/48	प्रत्येक मंत्रालय/विभाग अपने अधीनस्थ/संबद्ध/उपक्रमों/प्रतिष्ठानों/संगठनों में एक राजभाषा संवर्ग स्थापित कर अपने राजभाषा केंद्र से देश भर में स्थापित अपने सभी बड़े कार्यालयों में राजभाषा अधिकारी/कर्मचारी को तैनात कर सकते हैं। इससे उन्हें पदोन्नति के अवसर भी मिलेंगे।	यह सिफारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार की गई है कि जहां संभव हो वहां संवर्ग बनाया जाए तथा जहां संभव न हों वहां स्टाफ की पदोन्नति के लिए अन्य उचित व्यवस्था की जाए।	इस सिफारिश पर पारित राष्ट्रपति जी के आदेश यथावत हैं।
65	8/49	क्षेत्र 'ग' में हिंदी कार्मिक की नियुक्ति पर उसे विशेष भूत्ते के रूप में प्रोत्साहन राशि दी जानी चाहिए और साथ ही ऐसी तैनाती एक सीमित अवधि के लिए होनी चाहिए जिससे कि क्षेत्र 'क' के अभ्यर्थी बेझिङ्क क्षेत्र 'ग' में तैनाती स्वीकार कर लें।	सिफारिश स्वीकार नहीं की गई है।	इस सिफारिश पर पारित राष्ट्रपति जी के आदेश यथावत हैं।

66	8/56	रेडियो/टेलीविजन जैसे इलैक्ट्रानिक संचार माध्यमों के जरिए होने वाले शैक्षणिक प्रसारण केवल हिंदी में सुनिश्चित किए जाएं क्योंकि इनकी पहुंच दूर-दराज के क्षेत्रों तक रहती है।	देश में भाषायी विविधता को देखते हुए सिफारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि रेडियो/दूरदर्शन के जरिए भारत सरकार द्वारा प्रयोजित शैक्षणिक प्रसारणों में हिंदी माध्यम के प्रसारणों को समुचित/पर्याप्त समर्यावधि प्रदान की जाए।	इस सिफारिश पर पारित राष्ट्रपति जी के आदेश यथावत हैं।
67	8/58	केंद्र सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों, बैंकों और अन्य संस्थानों के विभागीय कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थानों में अत्यंत तकनीकी विषयों को छोड़कर सभी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हिंदी माध्यम से पढ़ाये जाने कि व्यवस्था की जाए।	सिफारिश एक संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि सभी सेवाकालीन प्रशिक्षणों को प्रमुखतः हिंदी भाषा के माध्यम से और गौणतः मिली-जुली भाषा के माध्यम से चलाया जाए।	इस सिफारिश पर पारित राष्ट्रपति जी के आदेश यथावत हैं।
68	8/69	अंग्रेजी के अखबार में भी हिंदी के विज्ञापन दिए जा सकते हैं और हिंदी के अखबार में अंग्रेजी के विज्ञापन दिए जा सकते हैं। अतः सभी कार्यालय विज्ञापनों को द्विभाषी रूप में दें।	सिफारिश स्वीकार नहीं की गई है।	इस सिफारिश पर पारित राष्ट्रपति जी के आदेश यथावत हैं।
69	8/70	विज्ञापन की कुल राशि का न्यूनतम 50% हिंदी पर खर्च किया जाए और 50% अंग्रेजी एवं प्रांतीय भाषाओं पर जाए।	यह सिफारिश इस संशोधन के साथ मान ली जाए कि सरकारी विज्ञापन की कुल राशि का एक निश्चित प्रतिशत केंद्रीय मंत्रालय/विभाग अपनी आवश्यकतानुसार हिंदी तथा अंग्रेजी में दिए जाने वाले विज्ञापनों के संबंध में निर्धारित करें।	इस सिफारिश पर नौवें खंड की सिफारिश सं 48 एवं 88 के संदर्भ में जारी आदेश यथावत रहेंगे।
70	8/74	वर्ष 2008 से केंद्रीय सरकारी सेवा में आने से पहले ही 'क', 'ख', 'ग' तथा 'घ' सभी वर्गों में होने वाली सीधी भर्ती के दौरान ही हिंदी संबंधी ज्ञान की न्यूनतम योग्यता निर्धारित की जाए ताकि बाद में प्रशिक्षण संबंधी तमाम परेशानियों एवं बाध्यताओं से बचा जा सके। हिंदी संबंधी न्यूनतम योग्यता भी 'क', 'ख' तथा 'ग' वर्ग के मामले में कम-से-कम दसवीं कक्षा अथवा उससे अधिक हो सकती है। वर्ग 'घ' के लिए यह योग्यता मिडिल/आठवीं कक्षा तक शिथिल की जा सकती है।	सिफारिश स्वीकार नहीं की गई है।	इस सिफारिश पर पारित राष्ट्रपति जी के आदेश यथावत हैं।
71	8/75	कर्मचारियों के हिंदी का ज्ञान एवं उनके द्वारा किए गए हिंदी कार्य का व्योरा क्रमशः सेवा पंजिका तथा गोपनीय रिपोर्ट में अंकित किया जाए। साथ ही, हिंदी संवर्ग को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के संवर्गों से संबन्धित पदोन्नतियों के लिए गठित विभागीय पदोन्नति समितियां, पदोन्नति के विचारार्थ अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किए गए	सिफारिश स्वीकार नहीं की गई है।	इस सिफारिश पर पारित राष्ट्रपति जी के आदेश यथावत हैं।

	हिंदी कार्य का मूल्यांकन कर उसे बोनस अंक प्रदान करें।	
--	--	--

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, सभी राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, उपराष्ट्रपति सचिवालय, नीति आयोग, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, भारत के उच्चतम न्यायालय के महारजिस्ट्रार के कार्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत के विधि आयोग तथा बार कॉर्ट्सिल ऑफ इंडिया आदि को भेजी जाए।

इस संकल्प को आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में भी प्रकाशित किया जाए।

बिपिन बिहारी
संयुक्त सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 12th December, 2017

No. 177-Pres/2017-The following amendment is made in the English version of this Secretariat Notification No. 94-Pres/72, dated the 5th August, 1972 published in Part I Section 1 of the Gazette of India on the 19th August, 1972 relating to the award of 'Vir Chakra':—

At. S. No. 30

For – MAJOR VINOD KUMAR SARDA (IC-6715) THE PARACHUTE REGIMENT

Read - MAJOR VINOD KUMAR SARDA (IC-13715) THE PARACHUTE REGIMENT

P. PRAVEEN SIDDHARTH
Officer on Special Duty

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE)

New Delhi, the 6th December 2017

RESOLUTION

No. 20012/2/2017-O.L.(Policy)- Part 1—The Committee of Parliament on Official Language was constituted in 1976 under the Section 4(1) of the Official Languages Act, 1963. The Committee submits its Report to the President from time to time relating to Ministry-wise/Region-wise assessment of the use of Hindi, on basis of review of the compliance of the section 3(3) of the Official Languages Act, 1963 and rule 5 of the Official Languages Rules, 1976 relating to correspondence in Hindi, publication, code-manual and training etc. in Hindi, purchase of Hindi books in Central Government Offices, computerization and Hindi, compulsory provision of Hindi knowledge in recruitment rules, availability of Hindi medium in academic and training institutions, expenditure on Hindi advertisements and use of Hindi for commercial activities etc. Orders of the President on First Report on the Committee were published in 1988 and in 2017 the Orders of the President were published on the Ninth Report of the Committee. As per the Orders of the President on Recommendation No. 2 of the Ninth Part, The Department of Official Language was directed to review the recommendations made in the previous eight parts which have not been accepted or accepted with modifications. Accordingly, the undersigned is directed to convey the Orders of the President :—

Second Part

[Previous orders were Circulated through Resolution No. 12015/34/87-O.L.(T) dated 29.03.1990]

Sr. No.	Part No./Recommendation No.	Recommendation	President's Previous Order	President's Revised Order
1	2/3 'B'	All the employees, who have not been trained in Hindi typing or Hindi stenography, should be given this training by the end of 1990 according to a time bound programme so that they can do the work of Hindi typing or Hindi stenography as required.	This part of recommendation has been accepted with the modification that all the employees yet to be trained in Hindi typing and Hindi stenography should be trained by the end of 1994-95 under a time bound programme. For this purpose, it would be necessary to raise the targets for Hindi stenographers and Hindi typist in Annual Programme drawn up by the Department of Official Language by about 20% every year.	President's Order on this recommendation is unchanged.
2	2/7 'A'	In all the offices in region 'A' and 'B' where only Roman teleprinters have been installed, Devanagri teleprinters should also be installed by June, 1988.	This recommendation has been accepted with the modification that since bilingual teleprinters/telex machines have since been developed and are also being manufactured on commercial basis,. It would be appropriate that the Roman teleprinters are replaced by bilingual telex machines.	This recommendation is irrelevant in the present context. Hence this recommendation is not accepted.

3	2/7 'B'	At the same time, development of Devanagari and Roman bilingual electronic teleprinters and telex should be expedited. It should be ensured that there is no delay in its development and after its successful testing, bilingual electronic teleprinters should be installed in place of the existing Roman electronic teleprinters. This work should be completed by the end of 1988.	This recommendation has also been accepted with modifications. The development of bilingual telex machine has also been completed and the time limit for replacing the existing Roman electronic teleprinter with bilingual electronic telex machines by the end of year 1988 has also expired. Therefore the Department of Telecommunications may raise the production capacity of English-Devanagari bilingual telex machines and also ensure that in the next three years i.e. by 30.9.1993 all the teleprinters/telexes in Government Offices are bilingual. The Department of Telecommunications may draw a time bound plan for this so that while on one hand bilingual telex machines should be available in offices at the earliest on the other hand these mainly used in Devanagari only.	This recommendation is irrelevant in the present context. Hence this recommendation is not accepted.
4	2/20 'B'	The Department of Electronics should be made a check-point for purchase of Computers, Word processors etc.	The recommendation of the committee has been accepted with the modification that the check-point for purchase of computers and word processors would be the Administrative Division of every Department and the check-point for any relaxation in this matter would be the Department of Official Language.	This recommendation is not accepted.
5	2/25	As the telegram is also a form of correspondence, the Committee is of the view that all official telegrams to the Central Government Offices, State Governments and their Offices and other individuals etc. in regions 'A', 'B' and notified offices located in region 'C' should be sent in Devanagri only.	The recommendation has been accepted with the modification that all the telegrams from the offices, located at the places where the facility of sending telegrams in Devanagri is available, should be sent in Hindi only as per the targets prescribed by the Department of Official Language every year.	This recommendation is not relevant in present context. Therefore it is not accepted.

Fourth Part

[Previous orders were Circulated through Resolution No. 12019/10/91-O.L.(Int.) dated 28.01.1992]

Sr. No.	Part No./Recommendation No.	Recommendation	President's Previous Order	President's Revised Order
6	4/2 'c'	The Committee has recommended that each Ministry/Department may organize All India Official Language Conference once in a year.	This recommendation of the committee has been accepted with the modification that such conferences may be held only after the economy restrictions imposed at the present by the Ministry of Finance in this regard have been lifted. The Department of Official Language may issue instructions in this connection in due course.	This recommendation is accepted with modification that every Ministry/Department should consider organizing an internal all India Official Language

			Conference in accordance with the present directions of Ministry of Finance.
7	4/6 (b)	The Committee has recommended that documents of Section 3(3) of the Official Language Act (except for the documents required to be placed before the Parliament), in region 'A' should be issued only in Hindi.	According to the provisions of Section 3(5) of the Official Language Act 1963, the provisions of Section 3(3) shall remain in force until resolutions for the discontinuance of the use of English language for the purposes mentioned therein, have been passed by the Legislatures of all those States which have not adopted Hindi as their Official Language until after considering the resolutions aforesaid, a resolution for such discontinuance is passed by each house of the Parliament. Therefore, at present it is not possible to accept this recommendation of the Committee.
8	4/8 (b)	The Committee has recommended that at least six meetings of the Official Language Implementation Committee constituted in each office should be organized during a year.	It is not feasible. Therefore, this recommendation has not been accepted. However in view of Committee's said recommendation, the Department of Official Language may request all the Ministries/Departments to ensure convening four meetings during a year (one each quarter) invariably, in their departments as well as in the offices under their control and also to ensure discussions/reviews in these meetings mainly regarding progressive use of the Official Language Hindi and the implementation of Annual Programme.
9	4/8 (C)	The Committee has recommended that a Hindi Advisory Committee should be constitutes for each Ministries/Department separately. These should be re-constituted from time to time, atleast four meetings should be held during a year and timely follow-up action should be taken in concrete shape on the recommendations of the committee.	This recommendation of the committee has been accepted with the modification that a joint committee should be reconstituted for comparatively smaller ministries/Departments. However, separate committee may be constituted for other Ministries/Departments. The Department of Official Language may decide the policy, after reviewing the position.
10	4/9 (a)	The Committee has recommended that the Agenda/Minutes and other connected material for holding meetings, conferences and seminars by every Office of the Government of India should be issued invariably in both the languages i.e. Hindi and English.	This recommendation has been accepted with the modification that the Agenda/Minutes etc. and the connected material to be circulated in Region 'A' may be issued only in Hindi. The Department of Official language may issue necessary directions in this regard.
11	4/10	The Committee has also recommended that the telegram issued by the Central Government Offices to the Offices located in Region 'A' and 'B' should be in Devanagri script and a beginning be	The recommendation of the Committee in respect of sending telegram in Devanagri has been accepted with a partial modification. Keeping in view the available resources, the Department of Official Language may fix the target

		made to send telegrams in Hindi in Region 'C' as well.	in the Annual Programme, for the telegrams to be sent to Region 'C' also on the analogy of Regions 'A' and 'B' and ensure its compliance by issuing directions to all the Ministries/Departments.	
12	4/16	The Committee has recommended that the headings of the registers available in all the Government Offices and of the service books of all categories of Officers and Employees should be bilingual and the entries therein should be made in Hindi. Further, the badges/emblems etc. on the uniforms of all the Government officers and employees in all the regions should, invariably, be in Hindi also. The names to be carved on the uniforms should also be in both the languages i.e. Hindi and English. In addition, the addresses on the envelopes to be sent to regions 'A' and 'B' should, invariably be written in Hindi.	This recommendation of the Committee has been accepted with partial modification. The entries in the registers/service books being maintained in the Central Government Offices situated in region 'A' and 'B' should be made in Hindi and such entries in the offices situated in region 'C' may, as far as possible, be made in Hindi. The instructions issued earlier in this regard by the Department of Official Language may be recirculated to all the Ministries/Departments/Offices etc. to ensure the implementation of these recommendations.	President's Order on this recommendation is unchanged.
13	4/19 (B)	The Committee has reiterated its recommendations made in the second and third parts of its report that in the perspective of the unity and integrity of the country and responsibility and importance of the Department of Official Language thereto, the Government of India should reorganize the Department of Official Language, strengthening it further and give it the status of a full-fledged Ministry to ensure an effective and active implementation of the official Language policy of the Government of India in all its Ministries/Departments/Offices/ Undertakings and Autonomous Bodies.	In view of the importance and purview of the Ministry of Home Affairs and its liaison with various State Governments. The Department of Official Language should continue to remain under Ministry of Home Affairs. Therefore, the above recommendations of the Committee have not been accepted. However, according to the recommendations of the Committee, the Deptt. Of Official Language should be further strengthened and made more efficient.	President's Order on this recommendation is unchanged.

Fifth Part

[Previous Orders were circulated through Resolution No. I/20012/4/92-O.L.(Policy-1) dated 24.11.1998]

Sr. No.	Part No./Recommendation No.	Recommendation	President's Previous Order	President's Revised Order
14	5/1	Action should be taken urgently by reorganizing the Department of Official Language of the Ministry of Home Affairs and giving it the status of a full-fledged Ministry in order to make it more strong and competent.	It may not be pragmatic to give the Department of Official Language the status of a full-fledged Ministry in view of the work allocated to it at present.	President's Order on this recommendation is unchanged.

15	5/5	Stringent action may be taken against those officers who in spite of being proficient in Hindi are violating	The Department of Official Language may issue direction to all the Ministries/Departments that they should motivate and encourage their senior officers, especially Deputy Secretaries and officers of equivalent rank and other officers senior to them to do their work in the Official Language Hindi.	President's Order on this recommendation is unchanged.
16	5/16	The Official Language of the concerned State or Hindi should be used in the judgments, decrees and orders of High Court. But arrangements should also be made so that the authoritative translation of each judgment is made available in both the languages. As long as English continues to be in vogue, arrangements for providing their authoritative translation in English may be made. However, the proceedings of the High Court may be conducted in the Official Language of the State or in Hindi or in English.	For the purpose of this recommendation, the present policy to act within the framework of the available provisions of the Constitution and the Official Language Act, 1963, is adequate.	President's Order on this recommendation is unchanged.
17	5/17	For providing authoritative Hindi translation of judgments delivered in the Official Language of the concerned State, the Union Government may provide special financial assistance to the concerned State Governments of non-Hindi speaking States.	For making available authenticated Hindi translation of judgments delivered in the State Official Languages of Non-Hindi speaking States, the concerned State Governments may themselves take action in this behalf by optimally utilizing own financial resources.	President's Order on this recommendation is unchanged.

Sixth Part

[Previous Orders were Circulated through Resolution No. 12021/02/2003-O.L.(Imp-2) dated 03.09.2004]

Sr. No.	Part No./Recommendation No.	Recommendation	President's Previous Order	President's Revised Order
18	6/11.5.10	Particular attention should be paid for the purchase of dictionaries, glossaries, help and reference-literatures and other books and the amount spent on it should be as per the laid down target.	This recommendation of the Committee has been accepted with the modification that out of the total funds made available to the libraries, 50% of the money left after the purchase of journals and reference literature may be spent on the purchase of Hindi books. It is obligatory to purchase all the books mentioned in list of Standard Hindi books will be made available to all Ministries/Departments from time to time by the Department of Official Language.	This recommendation is accepted with the modification that the orders of the President on recommendation No. 52 of Part 9 will prevail.
19	6/11.5.13	The compulsory English Question paper in all recruitment examinations should be abolished. The option of giving answers in English medium to a candidate should be given only under	The orders regarding opting Hindi as the medium for the interview already exist. But the recommendation with regard to dispensing with the compulsory English question paper and making Hindi as a medium of all	President's Order on this recommendation is unchanged.

		unavoidable circumstances. Similar rules should be applicable in interview also.	recruitment examination has not been accepted as this is against the spirit of the Official Language Resolution, 1968 passed by both the House of Parliament.	
20	6/11.5.17	In some of the towns the number of the members of the Town Official Language Implementation Committee is too large. The Committee of Parliament on Official Language, therefore, suggests that maximum number of members of the Town Official Language implementation Committee should be fixed as 40 and these Committees should be divided into two more Committees accordingly.	This recommendation of the Committee has been accepted with the modification that the Committees comprising 150 members or more than that may be bifurcated. Department of Official Language may issue direction in this regard.	This recommendation is accepted with the modification that those Town Official Language Committees with members more than 50 should be divided so that maximum numbers of the members should not exceed 50.
21	6/11.6.4	It should be ensured that communications received in Hindi from any region are replied to in Hindi.	This recommendation of the Committee has not been accepted because as per provisions of Article 346 of the Constitution, official language is to be used in correspondence etc.	This recommendation is accepted with the modification that all Ministries/Department should abide by the Rule 5 of the Official Languages Act, 1976.
22	6/11.6.8	At state level, electronic instruments equipments/computers etc. should be provided either in bilingual form or in Hindi only and their full utilization for doing work in Hindi should be ensured.	This recommendation of the Committee is not distinct.	President's Order on this recommendation is unchanged.
23	6/11.6.9	Procurement of only Roman typewriters/electronic equipments etc. should be banned.	This recommendation of the Committee is not accepted.	This recommendation is not relevant in present context. Therefore it is not accepted.
24	6/11.6.10	Provisions should be made to send information to Central Government Offices on telex, teleprinter etc. in Hindi and provisions should also be made to send the maximum telegrams, fax etc. in Devanagari	The said recommendation of the Committee is not accepted.	This recommendation is not relevant in present context. Therefore it is not accepted.
25	6/11.10.3	After imparting the training to work in Hindi through the workshops, the persons, who have attained proficiency and working knowledge of Hindi should do work in Hindi. If they start doing their work in Hindi, they should be given additional increment permanently	It is not feasible. Therefore, this recommendation of the Committee has not been accepted.	President's Order on this recommendation is unchanged.
26	6/11.10.6	The entry which has been made in their Service-books for not doing	At present, there is no provision for any punishment, Hence, the above	President's Order on this

		the work in Hindi may also be made in their Annual Confidential Report similarly by their officers and it may be mentioned that have acquired the training and ability to work in Hindi but they are deliberately not doing work in Hindi. It is a violation of Official Language Act. This matter should be taken into consideration specifically at the time of next promotion of the concerned employees.	recommendation of the Committee have not been accepted.	recommendation is unchanged.
27	6/11.10.7	The Officers/Employees, who are sent for training in Hindi, Hindi typing/Hindi stenography/translation/workshops training during the office hours by the Ministry/Subordinate office/attached office/Undertakings of the Govt. of India, should attend training regularly and it may be essential for them to work in Hindi after qualifying the examination. If they do not do so, whatever expenditure has been incurred during the period of their training, may be recovered by deducting from the salary of the Employees.	At present, there is no provision for any punishment, Hence, the above recommendation of the Committee have not been accepted.	President's Order on this recommendation is unchanged.
28	6/11.10.8	The person who does his all work in Hindi and takes part in any Department Examination of the Govt. of India, may be given extra special marks for his work in Hindi during his interview and for this special consideration may be given to him by Department/Promotional Committee.	India is a multilingual Country. The employees of the Central Government come from all linguistic communities. Hence such discrimination is not possible. This recommendation of the Committee has not been accepted.	President's Order on this recommendation is unchanged.
29	6/11.10.15	The supervision work regarding the use and propagation of the Official Language in Official business may be done at least under an Officer of Joint Secretary level.	This recommendation of the Committee could not be accepted, as there is no Joint Secretary level Officers in all the offices. Therefore, the present arrangement is sufficient.	President's Order on this recommendation is unchanged.
30	6/11.10.19	Rule 8(4) of Official Language rules, 1976 should be amended in such a manner that orders could be given to the Officers/Employees who have attained proficiency in Hindi to do their entire work in Hindi and the Officers/Employees having working knowledge of Hindi should do some items of work in Hindi as may be laid down.	The present arrangements under rule 8(4) of the Official Language Rules, 1976 are sufficient. Therefore, this recommendation of the Committee has not been accepted.	President's Order on this recommendation is unchanged.
31	6/11.10.21	A fixed percentage of work may be laid down for doing in Hindi on the bilingual electronic equipments.	Targets for various items relating to the official work to be transacted in official Language Hindi are fixed in the Annual Programme. Accordingly, the work is to be done in Hindi on bilingual electronic	President's Order on this recommendation is unchanged.

			equipment. There is no need to fix the percentage separately.	
32	6/11.10.22	For the Government of India's officers located in Region "A" & "B" forms & standard drafts printed or prepared in Hindi only should be used.	Under Rule 11 of The Official Language Rules, 1976 the provisions at present are sufficient. Therefore the recommendation of the Committee is not accepted.	President's Order on this recommendation is unchanged.
33	6/11.10.23	In the Government of India's offices located in Regions "A" and "B" stamps, name plates, sign boards, seals, letter heads, details of office to be written on the staff car and the visiting cards should be got prepared in Hindi only.	The present arrangement under Rule 11 of Official Language Rules, 1976 is sufficient. Therefore, the above recommendations of the Committee have not been accepted.	President's Order on this recommendation is unchanged.
34	6/11.10.25	Section 3(3) of the Official Language Act, 1963 may be amended in such a manner that the documents as mentioned under the above section to be issued to offices to offices located in Region "A" & "B" may be issued in Hindi only.	In the context of the provisions contained in Section 3(5) of the Official Language Act, such an action is not possible. Hence this recommendation has not been accepted.	President's Order on this recommendation is unchanged.
35	6/11.10.32	Each office should celebrate Hindi day at least once in a week in addition to celebration of Hindi day once in a year. On that day, all work in the office should be done in Hindi only. If in any special case, it becomes imperative to do work in English on that day, the concerned officer should sign on that letter/order in Hindi only.	It is not feasible. Targets are fixed in the annual programme issued by the Department of Official Language for transacting the official work of the Union in Hindi. Therefore, this recommendation has not been accepted.	President's Order on this recommendation is unchanged.

Seventh Part

[Previous Orders were Circulated through Resolution No. 11011/5/2003-O.L.(Research) dated 13.07.2005]

Sr. No.	Part No./Recommendation No.	Recommendation	President's Previous Order	President's Revised Order
36	7/16.5(a)	The Kendriya Hindi Samiti must be re-constituted every 3 years on schedule.	This recommendation has been accepted with the modification that the term of Kendriya Hindi Samiti will generally be 3 years but in special circumstances it may be extended or curtailed.	President's Order on this recommendation is unchanged.
37	7/16.5(c)	The Deputy Chairman and all 3 conveners of Sub-Committees of the Committee of Parliament on Official Language should be called as special invitees to the meetings of the Central Official Language Implementation Committee.	Central Official Language Implementation Committee is a Government officials committee, hence the recommendation has not been found acceptable.	President's Order on this recommendation is unchanged.
38	7/16.5.(e)	Constitution/reconstitution of the Hindi Salahkar Samitis should be done in time and their meetings should be held regularly.	This recommendation has been accepted with the modification that all Ministry/Departments are to constitute/reconstitute the Hindi Advisory Committee well in time and organize its meetings as the targets	President's Order on this recommendation is unchanged.

			fixed in the Annual Programme.	
39	7/16.5(j)	Three meetings of the Town Official Language Implementation Committee in a year should be held in different offices under the Chairmanship of the Head of the Committee and the last meeting should be held in the office of the Head of the Committee itself and a senior officer of the Deptt of Official Language should also be invited to attend that meeting, so that a review regarding the activities and progress made throughout the year could be undertaken and be brought to the notice of all concerned, and these should be overcome by a collective effort.	This recommendation has not been found acceptable. To organize Town Official Language Implementation Committee meetings at different venues is not feasible from the point of view of availability of venue and other resources.	President's Order on this recommendation is unchanged.
40	7/16.5(k)	Keeping in view the large number of members of various Town Official Language Implementation Committee in the cities where only one Town Official Implementation Committee exists, such Town Official Language Implementation Committee should be divided into three sub-committees under separate conveners under the Chairman, so that a pro-Hindi atmosphere should be created and awareness of the Official Language Rules etc. in all the members offices increased.	It has been ordered on the recommendation No. 11.5.17 of the VI report of the Committee of Parliament on Official Language that all such Town Official Language Implementation Committee may be divided into two, where members are 150 or more. It is not appropriate to change the set up at this stage.	This recommendation is accepted with the modification that the maximum number of members Town Official Language Implementation Committee should be 50 and in case it exceeds then on the basis of feasibility it should be divided. In case of division each Town Official Language Committee should have separate Chairman and Secretary.
41	7/16.7(b)	While granting permission to private publishers for publishing Government Publishers for publishing Government Publications, a condition be imposed on them that they will not publish such publication only in English and is should be made mandatory for them to publish these publications in Hindi and English in diglot form.	This recommendation has been accepted with the modification that all Government publications should be printed in diglot form, as far as possible.	President's Order on this recommendation is unchanged.
42	7/16.7(d)	In service training for the officers of the rank of Under Secretary and above for enhancement of their managerial skills should be conducted in Hindi.	This recommendation has been accepted with the modification that all in-service Training courses be conducted primarily in Hindi and secondarily though mixed medium.	President's Order on this recommendation is unchanged.
43	7/16.7(f)	Specific targets in respect of	This recommendation has been	The

		dictation in Hindi or for other work to be done in Hindi by the officers may be included in the Annual Programme of the Department of the Official Language and it should be made mandatory for them to keep a record of this work and it should be ensured that the same is reviewed at Headquarter/Ministry level.	accepted with the modification that officers provided with stenographic assistance may utilize their services fully. Department of Official Language may prescribe targets in the Annual Programme for giving dictation in Hindi by the officers.	recommendation is accepted.
44	7/16.8 (c)	Special incentive may be given to those, who undertake drafting in Hindi.	This recommendation is not accepted as draftsmen are regular Government Officials.	President's Order on this recommendation is unchanged.
45	7/16.9 (a)	Any person from outside the Government be appointed to the post of High Advisor to the Government of India, who would, not only be a permanent invitee to the Committee of Parliament on Official Language, but also be a permanent member of the Kendirya Hindi Samiti. The services of any scholar or any experienced person, as also one associated with the propagation of Hindi, should be taken for this purpose.	This recommendation is under consideration	This recommendation is not accepted.
46	7/16.10 (1)	Provision should be made to seek Government permission for getting the copyright by private publishers before printing of the Government publications/material, and if such a provision already exists, a condition to the effects that the publication shall be both in Hindi and English should be included therein before the permission is accorded by the Government or any office/department. If, on the basis of size etc, printing of any book/compilation in diglot form is not feasible, in such a situation a special mention should be made on the cover page of the English edition that the Hindi version of this edition is also available with the publisher/distributor.	This recommendation has been accepted with modification that all Government Publications may be published in diglot form, as far as possible.	President's Order on this recommendation is unchanged.
47	7/16.12 (a)	In the context of disinvestment, the committee recommends that status quo with regards to the Official Language policy should be maintained in these enterprises irrespective of the Government's large or small shareholding in them.	Department of Official Language may consult with the Ministries regarding this recommendation.	This recommendation is accepted.
48	7/16.12 (b)	Correspondence in Hindi with the Government should be made mandatory for those MNC's as well as Domestic Companies who use	Department of Official Language may consult with all concerned.	This recommendation is accepted with the modification

		Hindi to publicize and promote the sale of their products. At the same time the Government should also respond in Hindi.		that action should be taken through inspiration and encouragement.
--	--	--	--	--

Eighth Part

[Previous Orders were Circulated through Resolution No. I/20012/07/2005-O.L.(Policy-1) dated 13.07.2005]

Sr. No.	Part No./Recommendation No.	Recommendation	President's Previous Order	President's Revised Order
49	8/1(d)	There should be atleast three meetings of Hindi Advisory Committees annually.	This recommendation is accepted with modification that all Ministries/Departments should organize atleast two meetings of Hindi Advisory Committees annually. All should endeavor for more meetings.	President's Order on this recommendation is unchanged.
50	8/7	A minimum percentage of entries in Hindi in the registers may be fixed for the offices located in Region 'C' and the provision of making entries in Hindi "as far as possible" in the registers may be deleted.	This recommendation is accepted with the partial modification that the Central Government offices situated in region 'C' may continue their efforts in this direction as far as possible.	President's Order on this recommendation is unchanged.
51	8/12	The committee had recommended in the fourth part of its report that in Region "A" all documents, should be issued only in Hindi. Keeping in view the present position in Region "A" the Committee reiterates its recommendation that excluding the aforementioned documents, the compulsion of the use of English for all the documents under section 3(3) of the Official Language Act 1963 should be dispensed with, in Region "A". The Ministry of Home Affairs should take the initiative and talk to the States where Hindi has not been adopted as the Official Language. These States should be persuaded to grant Hindi the state of the Official Language alongwith their own State's Official Language.	For the present, in respect of this recommendation, compliance in accordance with the provisions of section 3(5) of the Official Languages Act, 1963 will continue.	President's Order on this recommendation is unchanged.
52	8/13	To ensure that training facilities are available to every office, the Department of Official Language should introduce an intensive drive for training in Hindi Language/Typing/Stenography through the Town Official Language implementation Committees.	This recommendation is accepted with the modification that the Town Official Language Implementation Committees may render all possible assistance in getting trained all the Central Government employees through Central Hindi Training Institute, a subordinate office of the Department of Official Language.	President's Order on this recommendation is unchanged.
53	8/17	For effective conduct of the TOLICs, the TOLIC Secretariat	The recommendation is accepted with them modification that the Town	President's Order on this

		may be provided on a permanent basis with adequate human resource and should also be equipped with modern facilities.	Official Language Implementation Committees, may mobilize required man-power and other facilities from internal resources available, with its member-offices for effective organization of their meetings.	recommendation is unchanged.
54	8/18	In order to enhance the Official Language activities, an annual conference of the Chairmen of the TOLICs should be organized in every region, and their involvement should also be ensured while determining the Official Language policy and the targets.	The recommendation is accepted with the modification that such meeting may be organized annually on regional basis.	President's Order on this recommendation is unchanged.
55	8/19	Some special schemes may be introduced to encourage publication of Hindi news papers/Hindi magazines and for those Hindi Journalist associated with them in the non-Hindi speaking areas especially in states like Tamilnadu, Kerala and Karnataka.	The recommendation is not accepted.	President's Order on this recommendation is unchanged.
56	8/20	Representation of a Senior Officer from the Department of Official Language, New Delhi may be made compulsory in the meeting of the TOLICs.	The recommendation is accepted with the modification that as far as possible, the participation of the Senior Officers of the Department of the Official Language may be ensured in the meetings of the Town Official Language Implementation Committees.	President's Order on this recommendation is unchanged.
57	8/21	Posting of at least one Hindi Staff may be made compulsory in each office of the Central Govt. located in Region "C".	In respect of this recommendation, action may be taken in accordance with the guidelines issued by Department of the Official Language regarding posting of minimum staff.	President's Order on this recommendation is unchanged.
58	8/28	For a more effective implementation of the Official Language Policy as well as proper compliance of the Presidential Orders on the recommendations of the Committee of Parliament of Official Language, the Committee recommends that the meetings of the Central Official Language Implementation Committee (COLIC) be held under the Chairmanship of the Cabinet Secretary and the Secretaries of the Ministries/Departments participate as its members. In the event of the Cabinet Secretary being the chairman of the COLIC, the Secretaries of the other Ministries/Departments would take the matter regarding implementation of Official Languages Rules, etc. with appropriate seriousness.	The recommendation is under consideration.	At present meetings are held under the Chairmanship of Secretary (Official Language) in which there seems to be no need to change. Hence this recommendation is not accepted.

59	8/29	To make Scientific, Technical and Research Literature in Hindi available at one place the Government should immediately establish Book Banks. These Book Banks should make such literature available to the consumers and user organizations or should provide them with information regarding sources of availability.	The recommendation is accepted with the modification that all the Ministries/Departments may ensure availability of sufficient Hindi literature about their work on technology, scientific research and various subjects relating to research and make available the information on sources of availability of this literature on their web-sites and through other possible means to facilitate its consumer and user organizations in obtaining the same.	President's Order on this recommendation is unchanged.
60	8/34	In the Annual Programme 2004-05 and thereafter the Department of Official Language has modified the target laid down for purchase of Hindi Books to exclude journals and standard reference books. The Committee feels this modification needs to be reviewed, as this exclusion if continued indefinitely will adversely impact the long term goal of Hindi.	At present, status quo may be maintained.	President's Order on this recommendation is unchanged.
61	8/36	A training crash course of minimum seven days, in Hindi for use on computers should be organized for those Deputy Secretaries and other higher officers who have been given the facility of computers, and targets may be fixed region-wise for the amount of work to be done in Hindi on the computers by them.	The recommendation is accepted with the modification that shorter duration crash programs may be conducted for Deputy Secretary/higher officers and they should use more and more Hindi in their work on computers.	President's Order on this recommendation is unchanged.
62	8/46	In the competitive exams conducted for recruitment in the Central Govt. a compulsory question paper of Hindi of the level of Matriculation or equivalent may be prescribed. A candidate not passing this paper may be disqualified.	The recommendation is not accepted.	President's Order on this recommendation is unchanged.
63	8/47	In the Central Secretariat Official Language service, status-quo may be maintained in respect of the posts of Director (DOL) in all the big Ministries/Departments and simultaneously the creation of higher posts of joint Secretary (OL) may also be considered.	The recommendation is not accepted.	President's Order on this recommendation is unchanged.
64	8/48	A separate Official Language Cadre be set up by each Ministry/Department, which would cater to all its Subordinate/Attached/Undertaking/Corporations/Establishments. The Ministry could post Hindi officers/employees from this cadre to its offices, big or	The recommendation is accepted with the modification that where possible, a cadre may be set up and where setting up of the cadre is not found possible, an alternative system should be put in place for ensuring promotional avenues for the staff.	President's Order on this recommendation is unchanged.

		small, located all over the country. This would also provide them with greater promotional opportunities.		
65	8/49	Special allowance as an incentive may be given for posting of Hindi personal in Region 'C' and at the same time the posting should be for a limited period only so that candidates from Region 'A' accept postings in Region 'C' without hesitation.	The recommendation is not accepted.	President's Order on this recommendation is unchanged.
66	8/56	Educational telecast through electronic medias like Radio/TV should be only in Hindi as these medias have a wide coverage.	In view of the language diversity in the country the recommendation is accepted with the modification that in educational broadcasts sponsored by the Government of India, Hindi broadcasts may be given adequate time.	President's Order on this recommendation is unchanged.
67	8/58	All the training courses, expect for major technical subjects, should be taught in Hindi medium in the departmental staff training institutes of the Central Government, PSUs, Banks and other institutions.	The recommendation is accepted with the modification that all the in-service training may be conducted primarily in Hindi and secondarily in the mixed language.	President's Order on this recommendation is unchanged.
68	8/69	Advertisement in Hindi can be given in English newspapers and similarly advertisement in English can be given in Hindi Newspapers. Therefore, all the offices should give advertisement in bi-lingual form to Hindi/English newspapers.	The recommendation is not accepted.	President's Order on this recommendation is unchanged.
69	8/70	A minimum of 50% of the total amount spent on advertisements be in Hindi and rest 50% be spent on advertisements in English and other regional languages.	The recommendation is accepted with the modification that a certain percentage of total expenditure on Government advertisements to be given in Hindi and English may be decided by Central Ministries/Departments according to their requirements.	On this recommendation President's Order on recommendation no. 48 & 88 of Part Nine will prevail.
70	8/74	In future, a minimum level of Hindi knowledge be fixed for direct recruitment to all the Groups, viz. 'A', 'B', 'C' and 'D', in order to avoid the difficulties and obligations of providing training. The minimum level of knowledge of Hindi necessary for recruitment to Group 'A', 'B' and 'C' may be specified as matriculation or higher. For Group 'D' it can be relaxed to Middle/Eighth class level.	The recommendation is not accepted.	President's Order on this recommendation is unchanged.
71	8/75	Details of Hindi knowledge and Hindi work done by the employees should also be reflected in their service books and ACRS respectively. Additionally, the Departmental Promotion	The recommendation is not accepted.	President's Order on this recommendation is unchanged.

		Committees constituted for considering the promotions of the different cadres, except Official Language cadre, should award bonus marks for the officer/employee, being considered for promotion, on the basis considered for promotion, on the basis of Hindi work done by him/her.		
--	--	--	--	--

ORDER

A copy of this Resolution be sent to all the Ministries and Departments of the Government of India, all State Governments and Union Territories, the President's Secretariat, the Vice President's Secretariat, the Cabinet Secretariat, the Prime Minister's Office, the Niti Aayog, the Comptroller and Auditor General of India, the Lok Sabha Secretariat, the Rajya Sabha Secretariat, the Registrar General of Supreme Court, the University Grants Commission, the Law Commission of India & the Bar Council of India etc.

This Resolution be published in the Gazette of India for general information.

BIPIN BEHARI
Joint Secretary

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एनआईटी, फरीदाबाद में
अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई-प्रकाशित, 2017
UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2017

www.dop.nic.in